DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
बुधवार, 5 जुलाई 2023
NAME OF NEWSPAPERS DATED

एलजी ने एनजीटी अध्यक्ष के साथ किया यमुना का निरीक्षण

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के साथ भारतीय नौसेना की नाव पर आईएसबीटी से आईटीओ बैराज तक यमुना का निरीक्षण किया। उनके साथ डीडीए, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने सफाई कार्यों का जायजा लिया।

बता दें कि बीते दिनों उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) के निर्देशों के तहत नदी के बाढ़ क्षेत्रों पर बड़े स्तर पर सफाई का काम किया गया है। इस कार्य में यमुना नदी और किनारों पर जमा सीवरेज की गाद निकाली गई। साथ ही बाढ़ क्षेत्र की सफाई की गई। वजीराबाद बैराज से आईटीओ बैराज तक बाढ़ के मैदानों की बहाली का काम पहले चरण में पूरा हो चुका है। यह कार्य इसी साल शुरू हुआ था। अब यमुना के अगले चरण के तहत आईटीओ बैराज से ओखला के बीच सफाई का अभियान चल रहा है।

यमुना का जायजा लेते उपराज्यपाल व एनजीटी के अध्यक्ष। अमर उजाला

आईएसबीटी से आईटीओ बैराज तक नौसेना की बोट से की यात्रा जल्द शुरू होगा जल मार्ग

इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि आईटीओ बैराज तक 11 किलोमीटर की दूरी पर सफाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि यमुना को फिर से पुराना रूप देकर जलमार्ग को शुरू किया जाएगा। इस कोशिश में सभी लोगों का साथ लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में यमुना के प्रति अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यमुना को पुनर्जीवित करने का प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे दिखाना शुरू हो गया है।

साफ हो रहा नजफगढ़ नाला

एलजी ने कहा कि नजफगढ़ नाले को साफ करने के लिए विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है। यह यमुना में प्रदूषण के लिए 68 फीसदी कारण बनती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की निगरानी के बाद करीब तीन दशकों के बाद नदी की सफाई का काम पूरा होता दिख रहा है।

THE HINDU
Wednesday, July 5, 2023
DELHI

Need to protect green areas, HC tells DDA

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Stressing the "need to protect the green areas", the High Court directed the Delhi Development Authority (DDA) not to destroy the natural grass at Siri Fort Sports Complex (SFSC) by replacing it with an artificial turf. Justice Najmi Waziri asked the DDA, which manages the SFSC, to not lay the turf.

The order came on a PIL by Sudhir Gupta, a permanent SFSC member, after the authority floated a tender to lay an artificial turf on the complex's football and hockey grounds, which currently has manicured natural grass.

The HC lauded the elderly Mr. Gupta for being a "vigilant and spirited citizen".

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

संक्षिप्त समाचार

उपराज्यपाल से की सांसद बिधूड़ी ने मुलाकात

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के विकास कार्य एवं जनसमस्याओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के साथ बैठक की। इस बैठक में उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण शुभाशीष पांडा सहित डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद रमेश बिधूड़ी ने बदरपुर विधानसभा में एनटीपीसी ईको पार्क के साथ डीडीए की खाली भूमि पर खेल मैदान, हरकेश नगर में डीडीए के 4 एकड़ पार्क में खेल मैदान, संगम विहार के-ब्लॉक डीडीए पार्क में खेल मैदान, तुगलकाबाद खेल मैदान में चेंजिंग रूम, दर्शक दीर्घा व शौचालय की व्यवस्था, इग्नू के पास मैदानगढ़ी रग्बी स्टेडियम को पूर्ण रूप से विकसित कर चेंजिग रूम, दशर्क दीर्घा व शौचालय की व्यवस्था, हरगोविंद एनक्लेव छतरपुर में डीडीए की लगभग 10 एकड़ खाली जमीन पर पार्क विकसित करने, विराट सिनेमा के पास अम्बेडकर नगर में फंक्शनल साइट जिसका कार्य पिछले 3 वर्षों से अधूरा है, उसे विकसित करवाने, गांव डेरा व घिटोरनी को मूलभूत सुविधानुसार विकसित करवाने, असोला गांव में खसरा नंबर 43 शामलात भूमि पर बारात घर का निर्माण, आया नगर व फतेहपुर बेरी में बारात घर निर्माण, दयनीय स्थिति में तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु आग्रह किया। इसके बाद उपराज्यपाल ने एक माह में इन सभी संबंधित कार्यों को पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

'यमुना के कायाकल्प के प्रयास देने लगे अच्छे परिणाम'

एलजी और एनजीटी के चेयरमैन ने आईटीओ बैराज तक नाव से लिया यमुना का जायजा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के साथ मंगलवार को आईएसबीटी से आईटीओ बैराज तक यमुना नदी का निरीक्षण किया। वे हाल ही में यमुना नदी आई भारतीय नौसेना की नाव में सवार थे। यमुना के इस खंड में जल परिवहन की पुष्टि पिछले महीने ही हुई थी। इसके बाद एलजी के आदेश पर भारतीय नौसेना की नाव यमुना नदी में आई। एलजी और एनजीटी के चेयरमैन के साथ डीडीए आई एंड एफसी, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न हितधारकों ने भी यमुना की सफाई को बारीकी से देखा। गौरतलब है कि एनजीटी द्वारा यमुना की सफाई के लिए 9 जनवरी 2023 को गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के दिशा निर्देश पर यमुना और यमुना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सफाई हो रही है। टीम के साथ विभिन्न धर्मा के पुजारी भी सम्मिलित थे। दरअसल, एनजीटी द्वारा गठित एचएलसी 8 विभिन्न कार्यान्वयन मापदंडों के माध्यम से यमुना नदी के कायाकल्प की निगरानी कर रही है। इनमें नदी और उसके दोनों किनारों पर जमा हुए सीवरेज के कारण यमुना से गाद निकालने के अलावा बाढ़ग्रस्त मैदानों की सफाई और पुनर्बहाली भी शामिल है। पहले चरण में वजीराबाद बैराज से लेकर आईटीओ बैराज तक बाढ़ग्रस्त मैदानों के कायाकल्प का काम इस साल फरवरी में शुरू हुआ था जो अब पूरा हो गया है। अब आईटीओ बैराज से लेकर ओखला तक के खंड पर सफाई का काम चल रहा है। यमुना के निरीक्षण के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि आईटीओ बैराज तक के 11 किलोमीटर खंड में यमुना की घाटों की सफाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है जिसे हर कोई देख सकता है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि यमुना के कायाकल्प के दीर्घकालिक समाधान में दिल्ली के आम लोगों को शामिल करना होगा और जब एक बार लोगों का यमुना नदी में नाव से परिवहन संभव हो सकेगा तो लोग स्वतः ही इसकी सफाई और कायाकल्प में शामिल हो जाएंगे। एलजी सक्सेना ने कहा, इससे लोगों में यमुना के प्रति अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद मिलेगी।

फोटो मिहिर सिंह

एलजी ने नजफगढ़ नाले की सफाई को विशेष रूप से रेखांकित किया

उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि यमुना नदी के कायाकल्प के लिए किए जा रहे प्रयास धीरे-धीरे ही सही परंतु निश्चित रूप से अब उत्साहजनक परिणाम दिखाने लगे हैं। अगर आप साल-दर-साल के आधार पर इसकी तुलना करें तो घाटों और पानी की गुणवत्ता में साफ अंतर दिख सकता है। एलजी ने नजफगढ़ नाले की सफाई को विशेष रूप रेखांकित किया जहा बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं।

एनजीटी निगरानी के बावजूद यमुना नदी की सफाई को किया गया नजरअंदाज

एलजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले तीन दशकों से सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की लगातार निगरानी के बावजूद यमुना नदी की सफाई को नजरअंदाज किया गया था। लेकिन अब काम ने गति पकड़ी है और निश्चित रूप से इसके परिणाम सामने आएंगे। हालांकि अभी लंबा रास्ता तय करना है। उपराज्यपाल के विशेष प्रयास से यमुना के कायाकल्प के लिए दिल्ली के लोगों को नदी के करीब लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनमें यमुना नदी के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा की गई है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY

P the pioneer

NAME OF NEWSP NEW DELHI I WEDNESDAY I JULY 5, 2023

LG, NGT chief inspect Yamuna's ISBT to ITO Barrage stretch

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi's Lieutenant Governor VK Saxena along with NGT Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel, conducted an inspection of the navigable stretch of the Yamuna river between ISBT and ITO Barrage. The inspection took place on a recently brought Indian Navy Boat, following its assessment of the stretch's navigability last month, as per the LG's request.

Accompanied by senior officials from stakeholder departments such as DDA, I&FC, MCD, and DJB, the LG and NGT Chairperson also assessed the progress of cleaning works on the river's floodplains, under the guidance of the High-Level Committee (HLC) established by the NGT on January 9.

The visiting team was joined by priests representing different faiths.The HLC has been monitoring the rejuvenation of the Yamuna river through eight distinct implementation parameters, including the cleaning and restoration of floodplains, as well as desiltation of accumulated sewerage in the river and its banks. The first phase of restoring the floodplains from Wazirabad Barrage to ITO Barrage began in February this year and has since been completed, while cleaning operations in the stretch between ITO Barrage and Okhla are currently underway. During the occasion, the LG highlighted the successful completion of cleaning works along the 11 km stretch until the ITO Barrage, visible for everyone to witness. He reiterated the need to involve the common residents of Delhi in any long-term solution for Yamuna's rejuvenation. Once the waterway becomes fully navigable, citizens can actively engage with the river, fostering a sense of belongingness towards the Yamuna, according to Saxena.

The LG emphasized that efforts to rejuvenate the river have gradually begun to yield encouraging results, evident in physical appearance of the ghats and improved water quality when compared on a year-to-year basis. Saxena specifically highlighted the extensive endeavors to clean Najafgarh Drain through desiltation and diversion of drains to Sewage Treatment Plants (STPs).

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
P CLIPPING SERVICE

the pioneer

NAME OF NEWSP NEW DELHI | WEDNESDAY | JULY 5, 2023

NGT panel to check air pollution around AIIMS

PNS ■ NEW DELHI

The National Green Tribunal (NGT) has formed a panel to monitor the implementation of the recommendations for checking air pollution in and around the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in a time-bound manner.

While entrusting the responsibility of adopting the measures required to reduce air pollution inside the campus to the medical institute's director, the tribunal has also constituted a separate panel to study identical issues at several other government hospitals in the national capital and issue appropriate Standard Operating Procedures (SOPs).

The NGT was hearing a petition claiming failure of the authorities concerned to control air pollution in and around premier healthcare institutions, including AIIMS Delhi, to the detriment of the health of patients, their attendants, doctors and staff. The NGT had in March formed a seven-member joint committee comprising the Central Pollution Control Board (CPCB), Deputy Commissioner of Police (Traffic), area divisional or District Forest Officer (DFO), Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Pollution Control Committee (DPCC), the AIIMS director or his nominee and a nominee of the Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital to make recommendations to remedy the situation. It said the committee has to file an action taken report within four months.

A bench of Chairperson Justice A K Goel accepted the report of the joint committee filed on July 1, and said the measures suggested had to be implemented in a time-bound manner.

The bench, also comprising judicial member Justice Sudhir Agarwal and expert member A Senthil Vel, said, "We also agree that a hospital complex being an environmentally sensitive area, an environmental management plan is required not only covering the campus but also the surrounding periphery. Prohibited and regulated activities need to be identified and mentioned in such a plan..." Regarding the measures to be adopted outside the AIIMS campus, including control of traffic congestion, removing encroachments, congestion at gates, speeding of vehicles, improving road conditions, control of dust and other sources of pollution, the bench constituted an eight-member joint committee.

The committee comprising representatives of the New Delhi Municipal Corporation (NDMC), Public Works Department (PWD), Delhi Development Authority (DDA), Delhi Police, city traffic police, AIIMS, CPCB, and DPCC has to prepare an action plan in light of the recommendations of the joint committee and to monitor its execution in a time bound manner, the bench said.

"Ambient air quality in and around the campus be monitored and as and when it exceeds the laid down parameters within 500 meters of the boundaries of AIIMS, regulatory measures be taken in the light of Graded Response Action Plan (GRAP).

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS NEW DELHI | WEDNESDAY, 5 JULY, 2023 ED----------

No artificial turf in Siri Fort Sports Complex, natural grass not be destroyed, says Delhi HC

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Observing that green area in the midst of a thickly populated residential place is of far greater value than a forest kilometres away from a human habitation, the Delhi High Court has directed the authorities to not destroy the natural grass in Siri Fort Sports Complex (SFSC) and covert it into artificial turf.

Justice Najmi Waziri said the proposed introduction of artificial turf by the Delhi Development Authority on the fields of the sporting complex was not only contrary to the judicial orders but also "impermissible and illegal".

"Such conversion of laying of artificial turf will have to be abandoned by the DDA. The direction of the Supreme Court and of the National Green Tribunal to DDA (to not cut the large number of trees in and around the SFSC) and to 'ensure that the entire complex is duly maintained' is of much significance and was for the purpose of protecting the greenery in the entire area," said the court in a recent order.

"The DDA shall maintain the status quo passed in this petition on 04.02.2020. The said order is made absolute. The football and hockey fields which presently have natural grass shall not be destroyed or altered to artificial turf," ordered the court.

The court said environment belongs to all humans and living creatures and while each living being needs to be protected from damaged ecology, there is also a shared duty and responsibility on each individual to protect the environment from harm.

The court's order was passed on a petition by Sudhir Gupta, a senior citizen of over 75 years of age, against the laying of artificial turf at SFSC by the DDA.

The DDA, which manages the sports centre and is the land owning agency, had floated a tender for conversion of football and hockey grounds, which have manicured natural grass, into a synthetic or artificial turf.

The petitioner, a permanent member of the SFSC and resident of the adjacent Asiad Village, argued the synthetic turf would be environmentally degrading, rob the sports centre of natural earth and harm the players and people in its vicinity.

He submitted large quantity of water is required just to keep the artificial turf soft, playable and cool in the heat and even internationally, there is a shift from artificial turf to natural grass for playing football and hockey.

The court, in its order, observed that in a city like Delhi, the ecology of small pockets of green areas, which serve as its lungs, is crucial and fragile and therefore greater caution and sensitivity has to be exercised.

It stressed that the land-owning agencies hold land in trust for future generations and "creeping concretisation, through seemingly innocuous projects, need to be examined from the prism of ecological balance".

"There can hardly be a case for this city being robbed of its green spaces in a few years only because in one project or the other, there is resultant concretisation of the earth. Today it is two sports fields, tomorrow it would be something else," it said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, JULY 5, 2023 ---DATED---

HC: Green space in city better than remote forest

Abhinav.Garg@timesgroup.com

New Delhi: A green space in the midst of a thickly-populated residential area is of far greater value than a forest "kilometres away from a human habitation", the Delhi high court has said, forbidding authorities from destroying the natural grass in Siri Fort Sports Complex (SFSC).

DDA planned to replace it with artificial turf in the hockey and football fields but was taken to court by a senior citizen who challenged the move.

"SFSC lies in the heart of South Delhi and the adjoining greenery needs to be protected at all costs, as the entire area is a green lung for the city," Justice Najmi Waziri observed in a recent order.

"The laying of artificial turf will be an irreversible damage to not only the football and hockey fields but to the contiguous green area and is likely to affect the people using the immediately adjacent walking path," the court noted.

▶ 'Green pkts crucial', P 5

'GRASS WILL STAY'

- DDA had proposed to **convert the grass in the football and hockey fields at Siri Fort Sports Complex** into artificial turf
- Delhi HC says ecology of city's green pockets is crucial, fragile. **Greater sensitivity** must be exercised
- Rules that these **sports fields "shall not be destroyed** or altered to artificial turf"

Ecology of green pockets in city crucial, says HC

Abhinav.Garg
@timesgroup.com

New Delhi: Ruling against DDA's plan to convert the natural grass in the football and hockey fields at Siri Fort Sports Complex to artificial turf, the high court underlined that in a city like Delhi, the ecology of small pockets of green areas, which serve as its lungs, is crucial and fragile and therefore greater caution and sensitivity has to be exercised.

"There can hardly be a case for this city being robbed of its green spaces in a few years only because in one project or the other, there is resultant concretisation of the earth. Today it is two sports fields, tomorrow it would be something else," Justice Najmi Waziri said, reminding DDA of its duty to ensure that the natural environment is maintained, safeguarded and improved.

"The environment is much larger than a simple football or hockey field... Development is not always the creation of roads, buildings, civic or industrial infrastructure etc. In a world of technology, travel and tearing hurry, development is also manifested in the retention of delicate ecology and green areas of a neighbourhood, so as to maintain the environmental equilibrium for posterity," the court said.

"Such conversion...of artificial turf will have to be abandoned by the DDA. The direction of the Supreme Court and of the National Green Tribunal to DDA (to not cut the large number of trees in and around the SFSC) and to 'ensure that the entire complex is duly maintained' is of much significance and was for the purpose of protecting the greenery in the entire area," Justice Waziri further noted.

"The football and hockey fields which presently have natural grass shall not be destroyed or altered to artificial turf," it directed, while hearing a plea by Sudhir Gupta.

The court also highlighted that recently, FIFA-related football World Cup events were held on natural grass and even Salt Lake Stadium in Kolkata, which earlier had an artificial turf, has replaced it with a natural grass field.

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2023 दैनिक जागरण

विविध गतिविधियां

विकास कार्यों को लेकर एलजी से मिले सांसद

उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ बैठक करते सांसद रमेश बिधूड़ी ● सौ. सांसद कार्यालय

जासं, दक्षिणी दिल्ली : सांसद श्री रमेश बिधूड़ी ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों एवं जनसमस्याओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर मंगलवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। इस बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शुभाशीष पांडा सहित डीडीए के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सांसद रमेश बिधूड़ी ने बदरपुर विधानसभा में एनटीपीसी ईको पार्क के साथ डीडीए की खाली भूमि पर स्पोर्ट्स ग्राउंड, हरकेश नगर में डीडीए के चार एकड़ पार्क में स्पोर्ट्स ग्राउंड, संगम विहार के-ब्लाक डीडीए पार्क में स्पोर्ट्स ग्राउंड, तुगलकाबाद स्पोर्ट्स ग्राउंड में चेंजिंग रूम, दर्शक दीर्घा व शौचालय की व्यवस्था, इग्नू के पास मैदानगढ़ी रग्बी स्टेडियम को पूर्णरूप से विकसित कर चेंजिग रूम, दर्शक दीर्घा व शौचालय की व्यवस्था, हरगोविंद एन्क्लेव छतरपुर में डीडीए की लगभग 10 एकड़ खाली जमीन पर पार्क विकसित करने, विराट सिनेमा के पास अंबेडकर नगर में फंक्शनल साइट का कार्य, डेरा गांव व घिटोरनी को मूलभूत सुविधानुसार विकसित करवाने, असोला गांव में खसरा नंबर 43 भूमि पर बारात घर का निर्माण, आया नगर व फतेहपुर बेरी में बारात घर निर्माण, हेतु आग्रह किया, जिसके पश्चात उपराज्यपाल ने एक माह में उक्त कार्य को पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
NAME OF NEWSPAPERS----------
। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 5 जुलाई 2023

कोटला मुबारकपुर। छज्जूपुरा। साकेत। उत्तम नगर। पीतमपुरा।।

डीडीए के फ्लैटों में बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठे

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पहले आओ, पहले पाओ के चौथे चरण की आवासीय योजना में लोग लगातार पंजीकरण कर रहे हैं। साथ ही, डीडीए के कॉल सेंटर में भी सभी श्रेणियों के फ्लैट की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं, फ्लैट देखने जा रहे लोगों ने बुनियादी ढांचे को लेकर सवाल उठाए हैं।

रोहिणी सेक्टर-34 और 35 के रूट में बिजली के खंभों पर लाइट की व्यवस्था न किए जाने को लेकर लोग चिंतित हैं। वहीं, नरेला के सेक्टर-जी7 और जी8 के रूट से जुड़ने वाली सभी सड़कों पर साइन बोर्ड की बेहतर व्यवस्था करने की भी मांग की जा रही है। रोहिणी सेक्टर-34 के पॉकेट 1,2,3 और 4 में 1,516 एलआईजी फ्लैट हैं।

एलजी और एनजीटी के चेयरपर्सन ने नेवी की बोट से किया मुआयना

यमुना में तैयार हुआ वॉटर-वे

Photos: PTI

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना और एनजीटी के चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल ने मंगलवार को नेवी की बोट में सवार होकर आईएसबीटी से आईटीओ बैराज तक यमुना नदी में तैयार किए गए वॉटर-वे का निरीक्षण किया। यमुना के इस पूरे स्ट्रेच को बोट चलाने के हिसाब से डिवेलप किया जा रहा है। पिछले महीने उप-राज्यपाल के आदेश पर नौसेना की बोट के जरिए यमुना के इस हिस्से में बोटिंग की संभावनाओं का पता लगाने का काम शुरू किया गया था। हालांकि, पहले दिन बोट नदी में जमी गाद में फंस गई थी, लेकिन बाद में इसका पूरे स्ट्रेच पर सफल परीक्षण किया गया। उसी के बाद मंगलवार को एलजी और एनजीटी के चेयरपर्सन ने इस स्ट्रेच का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डीडीए, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी समेत अन्य सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं को भी खासतौर से आमंत्रित किया गया था।

एलजी ने बताया कि आईएसबीटी कश्मीरी गेट स्थित कुदसिया घाट से लेकर आईटीओ स्थित बैराज तक यमुना के 11 किमी लंबे हिस्से की सफाई का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और कोई भी यहां आकर इसे देख सकता है। उन्होंने कहा कि यमुना को पुनर्जीवित करने के किसी भी दूरगामी उपाय की सफलता के लिए दिल्ली के आम लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। एक बार जब यह वॉटर-वे पूरी तरह चालू हो जाएगा, तो लोगों का यमुना नदी से जुड़ाव और बढ़ेगा और वे इसे साफ रखने में अपना और अधिक योगदान दे सकेंगे।

> ISBT से ITO बैराज तक के स्ट्रेच को बोट चलाने के हिसाब से डिवेलप किया जा रहा है

एलजी ने यमुना और उसके आस-पास के किनारों की स्वच्छता में हुए दिख रहे सुधार की सराहना करते हुए कहा कि अभी लंबा रास्ता तय करना है। घाटों के किनारे साफ-सफाई बेहतर हुई है और पानी भी पहले के मुकाबले काफी साफ हुआ है, जिसे लोग साफतौर से देख सकते हैं। आम लोगों के लिए यमुना में बोटिंग शुरू करने के मकसद से इस स्ट्रेच को वॉटर-वे के रूप में डिवेलप करने का काम शुरू किया गया है।

एलजी ने यमुना और उसके आस-पास के किनारों की सफाई में सुधार की तारीफ की

■ आईएसबीटी कश्मीरी गेट स्थित कुदसिया घाट से लेकर आईटीओ स्थित बैराज तक यमुना के 11 किमी लंबे हिस्से की सफाई का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया

■ घाटों के किनारे साफ-सफाई बेहतर हुई है और पानी भी पहले के मुकाबले काफी साफ हुआ है, जिसे लोग साफतौर से देख सकते हैं

सिर्फ ट्रीट किए सीवेज को ही यमुना में छोड़ा जाए : सौरभ

■ **विस, नई दिल्ली:** दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज मंगलवार को नजफगढ़ नाले की सफाई के काम का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गाद निकालने के काम का और पंटून पुल पर लगाए गए हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का मुआयना किया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि केवल ट्रीट किए सीवेज को ही यमुना में छोड़ा जाए। उन्होंने भूजल के माध्यम से जल संरक्षण की समस्या का समाधान निकालने पर भी जोर दिया।

> नजफगढ़ नाले की सफाई के काम को मंत्री ने देखा

निरीक्षण के दौरान सौरभ भारद्वाज ने पाया कि नजफगढ़ नाले की बड़े पैमाने पर डीसिल्टिंग की जा रही है। इस परियोजना पर 11.2 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। नजफगढ़ ड्रेन से हंप हटाने पर सरकार 20.8 करोड़ रुपये और ख्याला ब्रिज से बसई दारापुर ब्रिज तक गाद निकालने के लिए 13.9 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, JULY 5, 2023 -------DATED----------

NGT Sets Up Eight-Member Panel To Check Pollution Around AIIMS

HEALTH HAZARD: Directs It To Implement Recommendations Submitted By SPA

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The National Green Tribunal (NGT) has directed an eight-member joint committee to implement the recommendations submitted by School of Planning and Architecture (SPA) to check sources of pollution around AIIMS Delhi, which has impacted patients and staff. The tribunal has also asked the panel to monitor air quality in and around the hospital and, when required, put GRAP measures in place.

NGT, in its order dated July 3, also constituted a five-member joint committee, headed by secretary, health ministry, to check sources of pollution outside all government district hospitals or bigger facilities, including medical colleges.

In June, SPA conducted a survey on the directions of an NGT-appointed committee headed by Central Pollution Control Committee (CPCB) to assess pollution sources within a 500-metre radius of AIIMS. It found traffic congestion, irregular parking, encroachments, poor condition of service roads and vehicle-pedestrian conflicts as the major causes, following which it listed preventive measures, based on which the joint committee submitted a report.

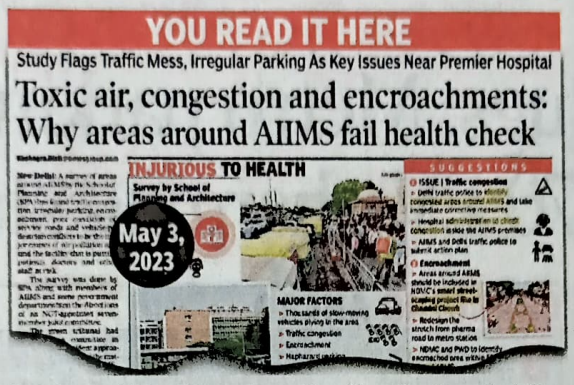

"Since there is no objection to the report of the joint committee, we accept it and issue directions to implement it," said the NGT bench headed by chairperson Adarsh Kumar Goel.

The order said a hospital complex requires an environment management plan for its premises as well as surrounding areas. The tribunal stated that prohibited and regulated activities need to be identified and mentioned in such a plan and a dedicated nodal agency is required for monitoring and funds.

"With regard to measures required to be adopted outside the AIIMS campus, such as control of traffic congestion, removing encroachments, congestion at gates, speeding of vehicles, improving road conditions, control of dust and other sources of pollution, we constitute an eight-member joint committee of traffic police, NDMC, PWD, DDA, Delhi Police, AIIMS, CPCB and DPCC to prepare an action plan in the light of the recommendations of the joint committee and monitor its execution in a time-bound manner," the order read.

NGT also asked the committee to monitor air quality in and around the campus and implement measures under GRAP within the 500-metre buffer zone when needed.

"The police commissioner and the AIIMS director will act jointly as the nodal agency for coordination and compliance... Execution of the plan may be reviewed periodically, preferably once a month, for the next six months. The first review meeting is to be held by August 31," the order stated.

The NGT bench said it was necessary to issue directions in this regard as there are identical issues in several other government hospitals, including Safdarjung Hospital. it added that an appropriate action plan should be prepared by the environment and health ministries after due consideration of the subject.

"We constitute a five-member joint committee to be headed by secretary, ministry of health, with representatives of ministries of environment, forest and climate change; urban development; and home affairs, not below the rank of joint secretary, and a nominee of CPCB not below the rank of director," the order read.

NGT ORDER SAYS

The police chief and the AIIMS director will act jointly as the nodal agency for coordination and compliance

The SPA study had found that traffic movement was slow within AIIMS and in the 500-metre buffer, leading to heavy emissions, dust and pollution. The survey analysed traffic movement and other aspects of major road stretches like MG Road, Ring Road, Sri Aurobindo Marg and areas like Yusuf Sarai, Gautam Nagar, Neeti Bagh, Masjid Moth, Gulmohar Park, parts of South Extension, Kidwai Nagar, Ansari Nagar and Green Park. It suggested a slew of measures for the AIIMS administration, NDMC, PWD and Delhi traffic police.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times DATED 05-7-2023

Aim to make Yamuna clean, fully navigable soon, says LG

Jasjeev Gandhiok
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant governor VK Saxena and National Green Tribunal (NGT) chairperson justice Adarsh Kumar Goel on Tuesday inspected an 11km stretch of the Yamuna between Kashmere Gate and the ITO barrage on boat — a stretch of the river whose navigability was ascertained by the Indian Navy last month.

The boat ride was undertaken on an Indian Navy boat, and senior officials from all stakeholder departments, including the Delhi Development Authority, the irrigation and flood control (I&FC) department, the Municipal Corporation of Delhi, and the Delhi Jal Board were also present.

Speaking after the inspection, Saxena, who heads an NGT-appointed high level committee on the Yamuna's rejuvenation, said once the waterway becomes fully navigable, it will allow the public to involve themselves at a physical level with the river.

After the inspection, Saxena said, "Cleaning works on the 11km stretch of the river till the ITO barrage had been successfully completed recently and is there for anyone to see. Any long-term solution to the rejuvenation of the Yamuna will have to involve the common residents of Delhi, and once the waterway becomes fully navigable, citizens could start involving themselves at physical level with the river. This, will help develop a sense of belongingness in the people towards the Yamuna."

Delhi LG VK Saxena and senior officials went on a boat ride on the Yamuna on Tuesday afternoon. SANJEEV VERMA/HT PHOTO

Last month, the Indian Navy had carried out a navigability assessment of the Yamuna. The assessment, completed on June 24, had revealed that the river's depth ranges between 0.9m and 4m. For the exercise, locally available amphibious desilting equipment was deployed, and an approximately 30m wide channel was created to make it easier for the boat to traverse the river.

Bhim Singh Rawat, a Yamuna activist and member of the South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP) said while such a plan will certainly connect people to the river, it will require sufficient environmental flow throughout the year.

"We will have to ensure desilting and dredging through the year. During the lean season, the Yamuna primarily receives water through drains and so the HLC needs to look at a way to sustain this water level," he said.

Scrap plans to lay synthetic turf at Siri Fort grounds: HC

Richa Banka
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Stressing the need to protect the environment, the Delhi high court has scrapped the Delhi Development Authority (DDA)'s project to convert natural grass football and hockey grounds at Siri Fort Sports Complex (SFSC) into artificial synthetic grounds.

"The proposed plan is impermissible and illegal. Therefore, such conversion of laying of artificial turf will have to be abandoned by the DDA... The laying of artificial turf will be an irreversible damage to not only the football and hockey fields but to the contiguous green area and is likely to affect the people using the immediately adjacent walking path," justice Najmi Waziri said. Making its February 4, 2020 order of status quo on the laying of artificial grass as "absolute", the court said that the fields which presently have natural grass shall not be destroyed or altered to artificial turf.

The court said that DDA's proposed plan would result in the destruction of a significant part of the open and naturally green area of the complex.

"In a city like Delhi, the ecology of small pockets of green areas is crucial and fragile. Therefore, greater caution and sensitivity has to be exercised," the court said in a judgment of June 30 made available on Monday. The court said that "irrespective of ownership of the land, DDA will need to protect the green areas especially in a city where increase in number of vehicles and dwelling units, adds to the environmental pressure and pollution".

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2023 ATED----------

मैदान में प्राकृतिक घास की जगह नहीं लगाया जाएगा सिंथेटिक टर्फ

हाई कोर्ट ने कहा, सिंथेटिक टर्फ से हरित क्षेत्र की क्षति होगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स (एसएफएससी) में प्राकृतिक घास वाले फुटबाल और हाकी मैदानों को सिंथेटिक टर्फ में बदलने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने कहा कि प्राकृतिक घास वाले फुटबाल और हाकी मैदानों को सेंथेटिक टर्फ में नहीं बदला जाएगा। न्यायमूर्ति वजीरी की पीठ ने कहा कि सिंथेटिक टर्फ बिछाने से न केवल खेल परिसर में फुटबाल और हाकी के मैदानों को बल्कि आसपास के हरित क्षेत्र को भी अपूरणीय क्षति होगी और इससे लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण फुटबाल के मैदान से अधिक महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि प्रस्तावित योजना न सिर्फ अस्वीकार्य है, बल्कि अवैध भी है।

हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का डीडीए को निर्देश है कि वह एसएफएससी के आसपास बड़ी संख्या में पेड़ों को न काटे और पूरे परिसर का उचित रखरखाव सुनिश्चित करे। हाई कोर्ट ने कहा कि भूमि व्यक्तियों और भूमि-स्वामी एजेंसियों की हो सकती है, लेकिन पर्यावरण सभी जीवित प्राणियों सहित सभी मनुष्यों का है। प्रत्येक जीवित प्राणी को क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी से बचाने की आवश्यकता है और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का साझा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि काम्प्लेक्स के आसपास की हरियाली को हर कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता है।

सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स●

75 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक व स्थायी सदस्यों की याचिका पर न्यायालय का आदेश

न्यायालय ने यह आदेश स्थानीय निवासी 75 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक सुधीर गुप्ता और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के स्थायी सदस्यों की याचिका पर दिया। याचिका में मैदानों को सिंथेटिक टर्फ में बदलने की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। भूमि का स्वामी होने के नाते डीडीए ने सिंथेटिक टर्फ के लिए एक निविदा जारी की थी। हालांकि, वर्ष 2020 में याचिका पर सुनवाई के पहले दिन प्राधिकरण की कार्रवाई पर यथास्थिति का आदेश दिया गया था।

न्यायालय ने कहा कि अगर डीडीए ने सिंथेटिक टर्फ की आवश्यकता का आकलन किया है तो वह इसे किसी अन्य स्थान पर बिछाने पर विचार कर सकता है। हालांकि, वहां भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सिंथेटिक टर्फ से स्थानीय पारिस्थितिकी को कोई खतरा या नुकसान न हो। भूमि के स्वामित्व के बावजूद डीडीए को विशेष रूप से ऐसे शहर में हरित क्षेत्रों की रक्षा करने की आवश्यकता होगी जहां लगातार बढ़ती आबादी के साथ वाहनों और आवास इकाइयों की संख्या में वृद्धि से पर्यावरणीय दबाव और प्रदूषण बढ़ता है।

सरकारी अस्पतालों के आसपास स्वच्छ वातावरण जरूरी : एनजीटी

- पर्यावरण प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में बनी पांच सदस्यीय समिति
- मरीजों, कर्मचारियों व अन्य आगंतुकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए साफ वातावरण आवश्यक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के आसपास प्रदूषण की समस्या से जुड़े आवेदन पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा कि एम्स के साथ ही सफदरजंग अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों के मरीजों, कर्मचारियों व अन्य आगंतुकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए स्वच्छ वातावरण जरूरी है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल व ए. सेंथिल वेल की पीठ कहा कि इस संबंध में अध्ययन व विषय पर विचार करने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को एक मानक आपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने की जरूरत है। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के अलावा शहरी विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव के स्तर के नामित अधिकारी व केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के निदेशक के रैंक के नामित अधिकारी को शामिल किया गया है।

एनजीटी ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कालेज के आसपास वातावरण प्रबंधन से जुड़ी जानकारी एक महीने में जुटा सकता है और उपलब्ध डाटा व जानकारी के आधार पर तीन महीने के अंदर एसओपी तैयार की जाए। एनजीटी ने आदेश दिया कि इससे जुड़ी कार्ययोजना स्वास्थ्य सचिव और पुलिस आयुक्त द्वारा चार महीने के अंदर एनजीटी के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष पेश की जाए। इसके साथ ही एनजीटी ने एम्स के आसपास वायु प्रदूषण के मामले में दाखिल स्थिति रिपोर्ट देखने के बाद आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। एनजीटी ने समिति को एम्स के बाहर अतिक्रमण, यातायात का भारी दबाव, वाहनों की तेज गति, सड़कों की स्थिति, धूल और प्रदूषण की समस्याओं का हल निकालने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।

एनजीटी ने कहा कि कार्ययोजना 31 जुलाई से पहले से तैयार की जाए और इस संबंध में पहली बैठक 15 जुलाई से पहले करें। इसके लिए एनजीटी ने पुलिस आयुक्त और एम्स निदेशक को संयुक्त रूप से नोडल एजेंसी बनाया है। एनजीटी ने कमेटी में एम्स, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), यातायात पुलिस, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस को शामिल किया है। एनजीटी ने कहा कि छह महीने में कार्ययोजना को लागू करने के लिए हर महीने बैठक करें। साथ ही पहली समीक्षा बैठक 31 अगस्त को करें और इसका कार्यवृत्त एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करें।

आवेदक गौरव शर्मा ने एनजीटी में आवेदन दाखिल करके एम्स के आसपास जाम व अतिक्रमण के कारण होने वाले वायु प्रदूषण पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इस पर अदालत ने संयुक्त कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस संबंध में स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के माध्यम से सर्वे कराकर एम्स के आसपास यातायात के भारी दबाव, अतिक्रमण, धूल और टूटी सड़कों पर सुझाव देते हुए विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। एनजीटी ने रिपोर्ट को देखने के बाद मंगलवार को अहम निर्देश पारित किए।